भारत की
कम्युनिस्ट
पार्टी
(मार्क्सवादी)

राजनीतिक-कार्यनीतिक लाइन की समीक्षा रिपोर्ट

21वीं कांग्रेस द्वारा स्वीकृत

(विशाखापट्टनम, 14-19 अप्रैल, 2015)

राजनीतिक-कार्यनीतिक लाइन की समीक्षा रिपोर्ट
21वीं कांग्रेस द्वारा स्वीकृत
(विशाखापट्टनम, 14-19 अप्रैल, 2015)

1. जून 2014 में हुयी केंद्रीय कमेटी की बैठक लोकसभा चुनावों की समीक्षा में इस नतीजे पर पहुंची थी कि कुछ समय से पार्टी आगे बढ़ने में विफल रही है और चुनाव में पार्टी के खराब प्रदर्शन में इसका प्रतिबिंबन हुआ है। इसलिए, केंद्रीय कमेटी द्वारा स्वीकृत समीक्षा रिपोर्ट में चार प्रमुख कदम उठाने का निर्णय लिया था। ये थे (i) जिस राजनीतिक-कार्यनीतिक लाइन पर हम चल रहे हैं उसका पुनरीक्षण (ii) पार्टी की सांगठनिक कार्यप्रणाली की समीक्षा तथा जनता के बीच कामकाज का पुनर्विन्यास, (iii) स्वतंत्र कार्यपणाली तथा राजनीतिक काम तथा पार्टी निर्माण को सुनिश्चित करने के लिए, जनसंगठनों एवं उनकी गतिविधियों की समीक्षा, (iv) उदारीकरण के बाद से सामाजिक-आर्थिक स्थितियों में आये बदलाव तथा उनके विभिन्न वर्गों पर हुए प्रभाव का अध्ययन करना ताकि उनके आधार पर ठोस नारे विकसित किये जा सकें। ये चारों कदम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इन पर एक साथ अमल- राजनीतिक एवं सांगठनिक- कमजोरियों को समाप्त करने तथा पार्टी को आगे बढ़ाने में मदद देगा।

2. केंद्रीय समिति इनमें से पहले कदम - राजनीतिक कार्यनीतिक लाइन (पी-टीएल) के पुनर्परीक्षण- का काम ले रही है। केंद्रीय समिति द्वारा स्वीकृत चुनाव समीक्षा रिपोर्ट ने कहा था ;

"पिछली पार्टी कांग्रेसों में लगातार हम पार्टी की स्वतंत्र शक्ति को बढ़ाने की बात करते रहे हैं। कुछ राज्यों ने हमारी स्वतंत्र शक्ति में आयी कमी की वजह पूंजीवादी राजनीतिक पार्टियों के साथ गठजोड़ करने की हमारी कार्यनीति को बताया है।

पार्टी की स्वतंत्र शक्ति का विकास कर पाने में विफलता हमारे द्वारा अमल में लाई जा रही राजनीतिक-कार्यनीति के पुनर्परीक्षण को आवश्यक बना देती है।"

3. 21 वीं पार्टी कांग्रेस की ओर बढ़ते हुए हम राजनीतिक-कार्यनीतिक लाइन (पी-टीएल) की आलोचनात्मक जांच-परख कर रहे हैं। यह कवायद हमारे लिए इस पार्टी कांग्रेस में मौजूदा सामयिक कारगर पी-टीएल के सूत्रीकरण में मददगार होगी। पी-टीएल के हिसाब से जिस अवधि की हमें समीक्षा करनी है वह गुजरे ढाई दशक की अवधि है। यह वह समय है जब सोवियत संघ का ध्वंस हुआ और परिणामत: अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के वर्ग संतुलन में बदलाव आया; जब नव-उदार दौर प्रकट हुआ और साम्राज्यवादी-वित्तीय पूंजी द्वारा संचालित वैश्वीकरण ने समाज पर सीधा असर डाला ; जब हिन्दुत्ववादी शक्तियों ने राजनीतिक ताकत हासिल की और जाति आधारित पहचान की राजनीति मुखर होकर सामने आयी। यह समय 13वीं पार्टी कांग्रेस से शुरू हुआ समय है।

4. 14वीं कांग्रेस ने ''कुछ विचारधारात्मक प्रश्नों पर'' प्रस्ताव स्वीकार किया था। इस प्रस्ताव ने सोवियत संघ के पराभव और समाजवादी व्यवस्था को लगे धक्कों के साथ आये भारी बदलाव सामने, हमारे विचारधारात्मक रुख का सूत्रीकरण किया था। हमने नयी परिस्थिति के संदर्भ में मार्क्सवादी-लेनिनवादी रुख को दोहराया था। आगे चलकर 20वीं कांग्रेस में हमने अपनी विचारधारात्मक समझ को, विशेष रूप से साम्राज्यवादी वैश्वीकरण तथा नवउदारवादी विचारधारा के बोलबाले के संदर्भ में अद्यतन किया था। ये विचारधारात्मक रुख पार्टी कार्यक्रम को अद्यतन बनाने में और इस दौर में राजनीतिक-कार्यनीतिक लाइनों का सूत्रबद्ध करने में मददगार रहे हैं।

5. राजनीतिक-कार्यनीतिक लाइन (पी-टीएल) वह कार्यनीति होती है जिसे हम अपने रणनीतिक लक्ष्य, जनता की जनवादी क्रान्ति तक पहुंचने के लिए, समय-समय पर अपनाते हैं। पूंजीवादी-सामंती राज का वामपंथी-जनवादी विकल्प प्रस्तुत करने के लिए वामपंथी-जनवादी मोर्चा कायम करने की कार्यनीति, हमने अपनी मौजूदा राजनीतिक-कार्यनीतिक लाइन (पी-टीएल) में निर्धारित की हुयी है। वामपंथी जनवादी विकल्प स्थापित करने का हमारा संघर्ष वर्गीय शक्तियों के पारस्परिक संबंधों में बदलाव लाने की हमारी कोशिशों का हिस्सा है, ताकि हम अपने रणनीतिक लक्ष्य की ओर अग्रसर हो सकें।

6. 13 वीं पार्टी कांग्रेस के बाद से अपनाई गयी पी–टीएल ने तात्कालिक परिस्थितियों से निबटने और फौरी खतरों का मुकाबला करने हेतु कार्यनीति बनाने तथा दांवपेंच अपनाने में मदद की। पी–टीएल ने सामर्थ्य दी जिससे हम अपनी सीमित शक्ति के बावजूद कांग्रेस सरकारों की जन–विरोधी नीतियों का कारगर तरीके से मुकाबला कर सके तथा राजीव गांधी की सरकार एवं बाद में नरसिम्हाराव की सरकार को पराजित करने की कार्यनीति बना सके। इसने साम्प्रदायिकता के खतरे के खिलाफ लड़ने तथा 1996 में भाजपा को सत्ता में आने से रोकने हेतु गैरकांग्रेसी शक्तियों को लामबंद करने में हमारी मदद की। इसके बाद 2004 में भाजपा नीत एनडीए गठबंधन को पराजित करने में इसने सही दिशा दी। यूपीए प्रथम की सरकार के दौर में हमारी इस कार्यनीतिक लाइन ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार क़ानून (नरेगा) और वनाधिकार कानून जैसे कुछ जनोन्मुखी कदमों को हासिल करने के लिए हुए संघर्षों को सही दिशा दी। इस दौर में एक के बाद एक अपनाई गयी कार्यनीतिक लाइनों ने पृथकतावाद, अंध–क्षेत्रीयतावाद तथा साम्राज्यवादी घुसपैठ का मुकाबला करने में सही दिशा दी। महिला, दलित, आदिवासियों के मुद्दों को उठाने और सामाजिक उत्पीड़न के खिलाफ लड़ने में भी इस कार्यनीति ने मदद पहुंचाई। पार्टी ने संघवाद को सुदृढ़ करने तथा केंद्र–राज्य सम्बन्धों को परिवर्तित करने में एक अविचल शक्ति की भूमिका निभाई।

7. कार्यनीतिक लाइन ने नव–उदार नीतियों के विरुद्ध संयुक्त प्रतिरोध का निर्माण करने का आह्वान किया था। 1991 के बाद से हुयी 15 अखिल भारतीय हड़तालें इस दौरान हासिल की गयी ट्रेड यूनियन एकता का परिणाम थीं। पिछले दो दशकों में चार वामपंथी पार्टियों के बीच एकता व समन्वय आगे बढ़ा है, और अधिक मजबूत हुआ है। विशेष तौर से इस दौरान अपनाई गयी कार्यनीति ने केरल तथा त्रिपुरा में वाम नेतृत्व वाली सरकारें कायम करने एवं पश्चिम बंगाल में वामपंथी सरकार के सुदृढ़ीकरण में मदद पहुंचाई। इन ढाई दशकों में विकसित एवं अमल में लाई गयी पी–टीएल का ही नतीजा, राष्ट्रीय राजनीति में, देश की सबसे बड़ी वामपंथी ताकत के रूप में सीपीआइ (एम) के बढ़ते हस्तक्षेप तथा भूमिका के रूप में सामने आया।

8. बहरहाल, जरूरत इस बात के आलोचनात्मक परीक्षण की है कि पी–टीएल ने पार्टी की स्वतंत्र शक्ति के विकास और वामपंथी–जनवादी मोर्चे के निर्माण के संघर्ष को कितनी मदद पहुंचाई है। हमें इन ढाई दशकों में इस पी–टीएल के क्रमिक विकास का यह पता लगाने के लिए परीक्षण करना होगा कि क्या ऐसी

कोई त्रुटि या ढील या परिपालन की कोई खामियां थीं जिनका पार्टी का स्वतंत्र विकास न होने में और वामपंथी जनवादी मोर्चे का निर्माण नहीं हो पाने में योगदान रहा हो।

वामपंथी एवं जनवादी मोर्चे की अवधारणा

9. वामपंथी एवं जनवादी मोर्चे की अवधारणा स्पष्ट रूप से सबसे पहले 10वीं पार्टी कांग्रेस में सूत्रबद्ध की गयी थी। इसके पहले 7 वीं से लेकर 9 वीं कांग्रेस तक हम कांग्रेस सरकार के जनवादी विकल्प का आह्वान करते रहे थे। 10 वीं पार्टी कांग्रेस के राजनीतिक प्रस्ताव ने वामपंथी एवं जनवादी मोर्चे की व्याख्या इस प्रकार की थी ;

"इस मोर्चे के निर्माण के लिए संघर्ष, वर्गीय शक्तियों के संतुलन में बदलाव लाने की हमारी कोशिशों का हिस्सा है, ताकि उस स्थिति को समाप्त किया जा सके जिसमें जनता के पास सिर्फ दो पूंजीवादी पार्टियों के बीच चुनाव और इस तरह मौजूदा प्रणाली में कैद रह जाने का ही विकल्प होता है। भविष्य में आगे बढ़ने के लिए सभी वामपंथी एवं जनवादी शक्तियों को एक साथ इकट्ठाकर पार्टी उन शक्तियों के सुदृढ़ीकरण की शुरुआत करती है, जो भविष्य में मजदूर वर्ग के नेतृत्व में बनने वाले जनता के जनवादी गठबंधन को आकार देने में हिस्सा लेंगी। वामपंथी-जनवादी मोर्चे को सिर्फ चुनावों या सरकारों के लिए बनाया गया गठबंधन नहीं समझना चाहिए, अपितु यह तात्कालिक -आर्थिक एवं राजनीतिक- बढ़त हासिल करने के लिए तथा अर्थव्यवस्था को अपनी जकड़ में लिए बैठी प्रतिक्रियावादी ताकतों को अलग-थलग करने के लिए, शक्तियों का एक संघर्षशील गठबंधन है।"

10. 10वीं पार्टी कांग्रेस के राजनीतिक प्रस्ताव ने वामपंथी जनवादी एकता की बुनियाद तैयार करने में जनसंघर्षों को छेड़ने की जरूरत तथा जन संगठनों की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया था,

"जब वामपंथी पार्टियां इन विराट जनसंगठनों को आम लड़ाई में उतारने में कामयाब हो जाएंगी, तभी एक वहनीय वामपंथी-जनवादी मोर्चे की संभावना बनेगी।"

11. दूसरे, इस प्रस्ताव ने : *"पूंजीवादी-सामंती पार्टियों के मंच और उनके व्यवहार से*

पूर्णतः भिन्न एवं उनके विरुद्ध एक राजनीतिक और आर्थिक कार्यक्रम लाने, उसे हासिल करने के लिए जनता की अगुआई करने, वामपंथी जनवादी शक्तियों द्वारा अवाम को इस काबिल बनाने कि वह पूंजीवादी सामंती राजनीतिक पार्टियों से दूर हट सके और लगातार बढ़ती तादाद में एक वैकल्पिक नेतृत्व के गिर्द लामबंद हो सकें", की जरूरत की ओर इशारा किया था।

12. तीसरे, दिसंबर 1978 में हुए सल्किया प्लेनम के संगठन पर प्रस्ताव ने पार्टी के विस्तार के अत्यंत महत्वपूर्ण कारक को इस प्रकार रखा था: "तथापि, जनवादी एकता की यह कायमी मेहनतकश जनता के सभी हिस्सों के बीच संगठनों तथा संघर्षों में अभूतपूर्व बढ़ोतरी की दरकार रखती है... इसी के साथ यह मजदूर वर्ग की पार्टी की ताकत - विभिन्न राज्यों में इसके सदस्यों की तादाद, उनकी भागीदारी के साथ जुझारू गतिविधियों, साम्राज्यवाद विरोधी, सामंतवाद विरोधी, एकाधिकार विरोधी एवं जनवादी शक्तियों के साथ उनकी एकता में भी, असाधारण बढ़ोतरी की अपेक्षा रखती।"

13. अंत में, 10वीं पार्टी कांग्रेस के राजनीतिक प्रस्ताव ने दृढ़तापूर्वक दोहराया कि: "इसलिए, मजदूर वर्ग और उसकी पार्टी की स्वतंत्र राजनीतिक गतिविधियां तथा उनका लगातार मजबूत होते जाना, वामपंथी एवं जनवादी ताकतों के मोर्चे के गठन के लिए जरूरी है।" इसी के साथ मोर्चे के अन्य घटकों के साथ वैचारिक संघर्ष भी जरूरी था ताकि पूंजीवादी एवं निम्न-पूंजीवादी विचारधाराओं के विरुद्ध मजदूर वर्ग की विचारधारा को मजबूती से सामने लाया जा सके।

वामपंथी एवं जनवादी मोर्चे का छोड़ दिया जाना

14. हमें यह भी जांचना-परखना होगा कि जिस पी-टीएल का हम पालन कर रहे थे क्या वह खुद वामपंथी एवं जनवादी मोर्चे के निर्माण हेतु किये जाने वाले प्रयासों को दिशा देने में हमारी सहायक थी। 10वीं पार्टी कांग्रेस के समय में, जब हमने वामपंथी एवं जनवादी मोर्चे का नारा निर्धारित किया था, पश्चिम बंगाल में वामपंथी मोर्चा था, त्रिपुरा में वामपंथी मोर्चा था और केरल में सीपीआइ(एम) के नेतृत्व में चलने वाला एक गठबंधन था, जो बाद में एलडीएफ बना। ये राष्ट्रीय स्तर पर बनाये जाने वाले वामपंथी एवं जनवादी मोर्चे की आंशिक अभिव्यक्तियां थीं। साढ़े तीन दशकों के बाद भी हम तीन राज्यों के इन मोर्चों से आगे नहीं जा सके हैं। जहां वामपंथी-जनवादी मोर्चे को कायम किया जाना था, उस अखिल भारतीय स्तर पर इस दिशा में कोई प्रगति नहीं है।

15. इसके कारणों की हमें पी–टीएल में ही तलाश करनी होगी। 13वीं कांग्रेस से हमने वामपंथी एवं धर्मनिरपेक्ष शक्तियों की एकता की बात शुरू की थी। हमने तात्कालिक परिस्थितियों का सामना करने के लिए गैर–कांग्रेसी धर्मनिरपेक्ष दलों का विकल्प बनाने तथा वामपंथी एवं जनवादी मोर्चा बनाने के कार्यभार में अंतर किया। 15वीं कांग्रेस में हमने वामपंथी, जनवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शक्तियों की एकता का नारा दिया। इस वक्त तक हम कमोबेश इस निष्कर्ष पर पहुंच चुके थे कि, वामपंथी एवं जनवादी मोर्चे का नारा, एक दूर का लक्ष्य है, न कि फौरन हासिल होने वाला लक्ष्य, जिसके रूप में उसे 11वीं पार्टी कांग्रेस द्वारा दोहराया गया था। इस तरह वामपंथी एवं जनवादी मोर्चे का नारा एक प्रचारात्मक नारा बनकर रह गया। वामपंथी, जनवादी एवं धर्मनिरपेक्ष गठबंधन, नया अंतरिम नारा बन गया। जहां यह पहले राजीव गांधी की सरकार के खिलाफ, भाजपा से अपने को अलग करते हुए, गैर–कांग्रेसी धर्मनिरपेक्ष पूंजीवादी पार्टियों की लामबंदी के रूप में शुरू हुआ था, बाद में भाजपा के विरुद्ध एक नारे में तब्दील हो गया। इसी के आधार पर हम 1996 में, सरकार में शामिल हुए बगैर, यूनाइटेड फ्रंट में शरीक हुए थे।

तीसरा विकल्प

16. यूनाइटेड फ्रंट के बिखरने के बाद, 16 वीं पार्टी कांग्रेस (1998) में हमने तीसरे विकल्प का नारा निर्धारित किया। इसके पीछे विचार वही, धर्मनिरपेक्ष पूंजीवादी पार्टियों (मुख्यतः क्षेत्रीय पार्टियों) के वामपंथी पार्टियों के साथ गठजोड़ का था। 17वीं पार्टी कांग्रेस में हमने साफ किया कि तीसरा विकल्प साझा न्यूनतम कार्यक्रम या निर्धारित की गयी नीतियों के आधार पर आएगा और यह सिर्फ चुनावी गठजोड़ नहीं हो सकता। 18वीं कांग्रेस तक हम इन पार्टियों को एक साझा न्यूनतम कार्यक्रम के आधार पर लामबंद करने की मुश्किलों को समझ चुके थे और हमने कहा कि धर्मनिरपेक्ष पूंजीवादी पार्टियों के दृष्टिकोण में बदलाव लाये बिना, तीसरे विकल्प की ओर बढ़ना मुमकिन नहीं है। 19वीं पार्टी कांग्रेस में हमने कहा कि सिर्फ संयुक्त आंदोलनों एवं संघर्षों के जरिये ही, धर्मनिरपेक्ष पूंजीवादी पार्टियों को प्रभावित कर, उन्हें एक साझा कार्यक्रम तक लाया जा सकता है।

17. चूंकि तीसरे विकल्प को हासिल करना और अलभ्य हो गया था, 18वीं पार्टी कांग्रेस के राजनीतिक प्रस्ताव में तीसरे विकल्प के निर्माण तथा चुनाव विशेष के लिए गैर–कांग्रेस धर्मनिरपेक्ष पार्टियों को शामिल कर चुनावी तालमेल के बीच

अंतर किया गया। इस तरह हमारे कामों में, वामपंथी–जनवादी मोर्चे का निर्माण खिसक कर तीसरे चरण पर आ गया। पहला चरण, तात्कालिक कार्यभार, चुनाव विशेष के लिए चुनावी तालमेल हेतु धर्मनिरपेक्ष पूंजीवादी पार्टियों को जुटाना हो गया। दूसरा चरण, साझा न्यूनतम कार्यक्रम पर आधारित तीसरे विकल्प का निर्माण था, जो संयुक्त आंदोलनों व संघर्षों के जरिये कायम किया जाना था। तीसरा चरण, वामपंथी–जनवादी मोर्चे का निर्माण था।

17वीं पार्टी कांग्रेस में की गयी समीक्षा

18. 1996 और 1998 दोनों ही चुनावों की समीक्षाओं में राजनीतिक कार्यनीतिक लाइन के पुनर्परीक्षण की बात कही गयी। यह इस तथ्य की रोशनी में किया गया कि कांग्रेस की पराजय के बाद पार्टी कोई उचित लाभ नहीं ले सकी थी, मुख्य फायदा भाजपा को हुआ था। हालांकि कुछ कोशिशें हुयीं, मगर पोलिट ब्यूरो सिर्फ पूंजीवादी पार्टियों के साथ संयुक्त मोर्चे की कार्यनीति पर पी–टीएल के अमल की समीक्षा कर पाया। 17वीं पार्टी कांग्रेस द्वारा की गयी समीक्षा ने पूंजीवादी पार्टियों के साथ – विशेषकर चुनावी दायरे में –संयुक्त मोर्चे की कार्यनीति की कमियों एवं कमजोरी को चिन्हांकित किया। इस समीक्षा में वामपंथी एवं जनवादी मोर्चे को हासिल करने की कार्यनीति पर चलने की बात काफी जोर देकर कही गयी। इसे वामपंथी एवं धर्मनिरपेक्ष पार्टियों की व्यापक एकता कायम करने के तात्कालिक कार्यभार और तीसरे विकल्प से भी अलगाया गया। बहरहाल, उल्लेखनीय रूप से इस समीक्षा में स्वीकार किया गया कि तात्कालिक कार्यभार का अनुसरण, एक स्वतंत्र भूमिका के विकास और वामपंथी एवं जनवादी शक्तियों के संघर्षों को आगे बढ़ाने के लिए नुकसानदेह साबित हो रहा था।

19. इसमें कहा गया था कि ;

"व्यवहार में तात्कालिक कार्यभार ही मुख्य व्यस्तता बन गया, जिसके चलते मौजूदा परिस्थितियों से उभरने वाले, तात्कालिक राजनीतिक एवं चुनावी कामों और राजनीतिक कार्यनीतिक लाइन में निर्धारित पार्टी की स्वतंत्र गतिविधियों तथा वामपंथी एवं जनवादी शक्तियों के संघर्षों के विकास के उतने ही महत्वपूर्ण बुनियादी कार्यभारों के बीच सम्बन्ध टूट गया है। (17वीं कांग्रेस में संयुक्त मोर्चे की कार्यनीति के सन्दर्भ में राजनीतिक–कार्यनीतिक लाइन की समीक्षा)

तीसरे विकल्प का त्याग

20. तब भी मौजूदा कार्यभार के रूप में वामपंथी–जनवादी मोर्चे के कार्यनीतिक लक्ष्य के साथ तीसरे विकल्प की कायमी के प्रयास जारी रखने का काम पी–टीएल में बना रहा। बार–बार के प्रयासों के बाद और इस आह्वान को दिए हुए पंद्रह साल बीत जाने के बाद भी जब व्यावहारिक रूप में कोई विकल्प उभर कर नहीं आया, अंततः 20 वीं पार्टी कांग्रेस में हमने तीसरे मोर्चे के अनुभवों की समीक्षा की। यहां हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि किसी कार्यक्रम के आधार पर इन सभी विपक्षी धर्मनिरपेक्ष पार्टियों को लामबंद कर पाना व्यावहारिक नहीं है और इस नारे को त्याग दिया गया। हमने दोहराया कि मुख्य प्रयास वामपंथी–जनवादी मोर्चे के निर्माण के लिए किये जाने चाहिए। जहां तक चुनावी कार्यनीति का प्रश्न था, राजनीतिक प्रस्ताव में कहा गया कि पार्टी के हितों को दृष्टिगत रखते हुए जिन राज्यों में जरूरी हो, हम धर्मनिरपेक्ष पार्टियों के साथ गठबंधन में शामिल हो सकते हैं।

21. जहां 15 वीं पार्टी कांग्रेस के बाद से अपनाई गयी पी–टीएल ने तबकी परिस्थितियों का सामना करने, फौरी खतरों का मुकाबला करने हेतु चुनावी कार्यनीति एवं संसदीय दांव–पेंच निर्धारित करने में हमारी मदद की, वहीं यह दर्ज किया जाना चाहिए कि इन तात्कालिक कामों में तल्लीनता ने पार्टी की स्वतंत्र शक्ति के विकास में कोई ज्यादा मदद नहीं की। इसके बिना राजनीतिक शक्तियों के संतुलन में कोई बदलाव नहीं लाया जा सकता था। शक्ति संतुलन दो मुख्य पूंजीवादी राजनीतिक पार्टियों- कांग्रेस और भाजपा-के इर्द–गिर्द घूमता रहा। अगर भाजपा को 1996 में केंद्र में सत्ता में आने से रोका जा सका तो इसने 1998 और 1999 में सरकार बनाने में सफलता प्राप्त कर ली। 2004 में भाजपा–एनडीए की पराजय का परिणाम कांग्रेस नीत यूपीए सरकार के 10 साल के रूप में आया, तो उसके बाद 2014 में भाजपा पहले से भी बड़ी ताकत के साथ वापस आ गयी। यह सब पार्टी की स्वतंत्र शक्ति को बढ़ा पाने तथा वामपंथी–जनवादी शक्तियों को आगे ले जाने में विफलता को रेखांकित करता है।

22. वास्तविकता यह है कि इस पूरे काल में जब हम तीसरे विकल्प की बात कर रहे थे, पार्टी की स्वतंत्र शक्ति नहीं बढ़ी। यह तथ्य खुद अपने आप ही अन्य धर्मनिरपेक्ष पूंजीवादी पार्टियों को लामबंद करने की संभावना को क्षीण कर देता है। चूंकि इस अवधि में पार्टी की स्वतंत्र शक्ति नहीं बढ़ी इसलिए राज्यों में इन

पार्टियों को चुनावी गठबंधनों के लिए समेट पाना भी कठिन हो गया। हाल के लोकसभा चुनावों में अनेक क्षेत्रीय पार्टियां हमारे साथ किसी भी तरह के चुनावी तालमेल के प्रति अनिच्छुक थीं। जहां तक धर्मनिरपेक्ष पूंजीवादी पार्टियों की बात है तो अखिल भारतीय स्तर पर ऐसी कोई धर्मनिरपेक्ष पूंजीवादी पार्टी नहीं है। लिहाजा तीसरे विकल्प के लिए वामपंथी, जनवादी और धर्मनिरपेक्ष पार्टियों की एकता कायम करने के प्रयास मुख्यत: क्षेत्रीय दलों तक केंद्रित रहे हैं।

क्षेत्रीय पार्टियों की भूमिका

23. क्षेत्रीय पार्टियों के बारे में, 1960 से ही हमारी समझ यह रही है कि ये पार्टियां क्षेत्रीय पूंजीपति-सामंती वर्गों का प्रतिनिधित्व करती हैं। इनका बड़े पूंजीपति वर्ग के साथ अंतर्विरोध है तथा इन्हें कांग्रेस सरकार के खिलाफ एवं राज्यों के अधिकारों के सवाल पर, लामबंद किया जा सकता है। 1967 के केंद्रीय समिति के दस्तावेज "नयी परिस्थितियां और कार्यभार" में हमने इनकी भूमिका को स्पष्ट किया था। मगर उदारीकरण तथा नवउदार नीतियों के आगमन के बाद से क्षेत्रीय पार्टियों की भूमिका में भी बदलाव आया है। इसे हमने 16वीं तथा 17 वीं पार्टी कांग्रेसों में दर्ज किया था :

"पूंजीवाद के विस्तार के बाद क्षेत्रीय पूंजीवादी-सामंती वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाली क्षेत्रीय पार्टियों के दृष्टिकोण में परिवर्तन आया है। चूंकि क्षेत्रीय पूंजीपति इनमें अपने स्वार्थों के और विकास की सम्भावनाएं देख रहे हैं इसलिए ये पार्टियां विदेशी पूंजी के प्रति अपना रुख बदल रही हैं और उदारीकरण नीतियों के प्रति अनुकूल हो रही हैं।" (राजनीतिक प्रस्ताव : 17 वी पार्टी कांग्रेस 2002)

24. वैश्वीकरण के असर से और नव-उदार नीतियों के दौर में, क्षेत्रीय पूंजीपतियों के कुछ हिस्से बड़े पूंजीपति की कतारों में दाखिल हो रहे हैं। और भी यह कि, गैर-बड़े पूंजीपति और बड़े पूंजीपति के बीच का अंतर्विरोध कुंद हो गया है। इसी का नतीजा है कि क्षेत्रीय पार्टियां नवउदार नीतियां अंगीकार करती जा रही हैं। हाल के वर्षों में हमने देखा है कि ये पार्टियां आर्थिक नीतियों के विरुद्ध किसी भी साझे मंच पर आने को तैयार नहीं हैं। इसके आगे भी, चूंकि ये पार्टियां ग्रामीण धनाढ्यों के गठजोड़ का प्रतिनिधित्व करती हैं, इसलिए गरीब किसानों तथा खेत मजदूरों के मुद्दों पर उनका रवैया भिन्न है। वे कांग्रेस और भाजपा से गठबंधन के मामले में भी लगातार, जब जैसा माफिक लगता है वैसा, अवसरवादी रुख अख्तियार

करती रही हैं। इसके बावजूद, हम उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर वैकल्पिक नीतियों के आधार पर लामबंद करने की नीति का अनुसरण करते रहे हैं। यह गलत और अवास्तविक साबित हुआ है।

संयुक्त मोर्चे की कार्यनीति

25. 7 वीं पार्टी कांग्रेस के बाद से ही हम लगातार संयुक्त कार्यवाहियों के महत्व पर जोर देते रहे हैं। वर्गीय संगठनों एवं जनसंगठनों की संयुक्त कार्यवाहियां तथा पार्टी स्तर पर संयुक्त आंदोलनों का विकास, हमारी पहुंच जनता के उन हिस्सों तक कराता है, जो पूंजीवादी पार्टियों के प्रभाव में हैं। हमें, जहां भी संभव है वहां, क्षेत्रीय पार्टियों के साथ संयुक्त कार्यवाहियों से हिचकिचाना नहीं चाहिए। यह वह पहलू है जिस पर जोर दिया जाना चाहिए। इसका पार्टी की स्वतंत्र भूमिका एवं ताकत के विकास के साथ सीधा सम्बन्ध है। परन्तु धर्मनिरपेक्ष पूंजीवादी पार्टियों के रवैय्ये के चलते, उनके साथ हमारी संयुक्त कार्यवाहियां कमोबेश चुनावी संग्राम तक ही सीमित रही हैं। हमारी कोशिशों के बावजूद, क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टियां जनता के मुद्दों पर साझी कार्यवाहियों और संघर्षों में शामिल होने के लिए तैयार नहीं हुईं। केवल चुनाव के पहले, जब कोई चुनावी गठबंधन बनने की ओर अग्रसर होता है तब ही, वे कुछ साझे अभियानों और सभाओं के लिए तत्पर होती हैं।

26. कई बार भाजपा के खिलाफ वामपंथी, जनवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शक्तियों की एकता कायम करने का रुख कांग्रेस के साथ तालमेल की ओर चला जाता है। यह 2004 के आंध्रप्रदेश विधानसभा चुनावों में कांग्रेस के साथ चुनावी समझदारी तक पहुंच गया। बाद में ओडिशा, पंजाब और महाराष्ट्र में कांग्रेस के साथ चुनावी तालमेल हुए। यह 17वीं पार्टी कांग्रेस (2002) में निर्धारित समझदारी के खिलाफ था, जिसमें कहा गया था कि लड़ाई का मुख्य निशाना भाजपा होगी किन्तु कांग्रेस के साथ किसी भी तरह का तालमेल या गठबंधन नहीं किया जाएगा।

राज्यों में वामपंथी-जनवादी मोर्चों का विकास

27. राष्ट्रीय पैमाने पर तीसरा विकल्प अथवा वामपंथी, जनवादी एवं धर्मनिरपेक्ष विकल्प पेश करने के प्रयत्न पार्टी की स्वतंत्र भूमिका को विकसित करने के मामले में हितकर नहीं रहे। वामपंथी-जनवादी मोर्चे को उभारने का काम, एक विकल्प के

रूप में धर्मनिरपेक्ष पूंजीवादी पार्टियों के साथ गठबंधन की कोशिशों के चलते बाधित हुआ था। फौरी स्थिति का सामना करने के लिए तीसरे विकल्प के निर्माण की कार्यनीतिक लाइन ने पूंजीवादी-सामंती राजनीतिक पार्टियों की नीति एवं व्यवहार से साफ़ तौर पर अलग एवं दृढ़तापूर्वक उनके विरुद्ध, राजनीतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने के काम को, अपने आधीन कर दिया। पूंजीवादी-सामंती पार्टियों (राज्य की प्रमुख क्षेत्रीय पार्टी सहित) के कार्यक्रम एवं व्यवहार से भिन्न कार्यक्रम लाये बिना, उसके आधार पर ठोस नारे एवं मांगों को लेकर आंदोलन तथा संघर्ष छेड़े बिना, इन पूंजीवादी राजनीतिक पार्टियों के पीछे चलने वाले अवाम को जीत पाना संभव नहीं है।

28. जहां वामपंथी नेतृत्व वाला मोर्चा मौजूद है उन मजबूत राज्यों में, छोटी पूंजीवादी पार्टियों के साथ जाने से वामपंथी-जनवादी कार्यक्रम को सामने लाने पर कोई असर नहीं पड़ता। किन्तु कमजोर राज्यों में, कहीं ज्यादा मजबूत क्षेत्रीय पार्टियों के साथ जाने से, वामपंथी-जनवादी कार्यक्रम को सामने रखने में बाधा उत्पन्न होती है। जिन वर्गों को हम वामपंथी-जनवादी मोर्चे के लिए लामबंद करना चाहते हैं, अक्सर, उनके आंदोलन क्षेत्रीय पार्टियों द्वारा चलाई जाने वाली राज्य सरकारों के विरुद्ध होते हैं। कुछ राज्यों में क्षेत्रीय पार्टियां, कांग्रेस तथा भाजपा से कहीं अधिक ताकतवर हैं कई बार हमें अपने अभियान और संघर्ष इस प्रभावी क्षेत्रीय पार्टी के विरुद्ध चलाने होते हैं। हमें ध्यान रखना होगा कि जिस तरह पश्चिम बंगाल, केरल तथा त्रिपुरा में वामपंथी-जनवादी मोर्चे आगे बढे हैं, कार्यनीतिक लाइन को उसी तरह की दिशा, अन्य राज्यों में भी वामपंथी-जनवादी शक्तियों को लामबंद करने के लिए देनी चाहिए। राष्ट्रीय स्तर पर चुनावी गठजोड़ के लिए धर्मनिरपेक्ष पूंजीवादी पार्टियों को इकट्ठा करने की हमारी अखिल भारतीय लाइन अक्सर राज्यों की वामपंथी-जनवादी शक्तियों को लामबंद करने के हमारे काम से ध्यान हटाती है।

29. जिन राज्यों में भी पार्टी के हित में और वामपंथी-जनवादी शक्तियों को लामबंद करने के हित में हो, पार्टी क्षेत्रीय पार्टियों के साथ समझदारी बनाने की समुचित चुनावी कार्यनीति तय कर सकती है। बहरहाल, इसे धर्मनिरपेक्ष पूंजीवादी राजनीतिक पार्टियों के साथ राष्ट्रीय गठबंधन की किसी अखिल भारतीय नीति से निर्देशित नहीं होना चाहिए। किसी भी तरह की चुनावी समझदारी में शामिल होते समय हमें 17वीं कांग्रेस की समीक्षा रिपोर्ट में निर्धारित किये गए सही दृष्टिकोण को भी ध्यान में रखना चाहिए।

लचीली कार्यनीति

30. राजनीतिक परिस्थितियों में तीव्र बदलाव हो सकते हैं। पूंजीवादी पार्टियों के बीच, उनके भीतर, नए अंतर्विरोध उभर सकते हैं। पार्टियों में विभाजन या नयी पार्टी बनाने के लिए साथ आने की वजह से राजनीतिक पार्टियां बदलाव के दौर से गुजर सकती हैं। ऐसी स्थिति का सामना करने के लिए लचीली कार्यनीतियां विकसित की जानी चाहिए। संयुक्त कार्यवाहियों की हमारी कोशिशों में विभिन्न सामाजिक आंदोलनों, जन-लामबंदियों तथा मुद्दा-आधारित आंदोलनों के साथ, संयुक्त मंचों के निर्माण की जरूरत पड़ सकती है।

स्वतंत्र शक्ति

31. पिछले दो दशकों में हुई सभी पार्टी कांग्रेसों में हम पार्टी की स्वतंत्र शक्ति को बढ़ाने पर जोर देते रहे हैं। पार्टी की स्वतंत्र भूमिका तथा गतिविधियों का विस्तार करके और बुनियादी वर्गों में काम करके ही पार्टी को एक अखिल भारतीय शक्ति बनाने की ओर बढ़ा जा सकता है। जैसा कि साल्किया प्लेनम ने कहा है, यह वामपंथी-जनवादी मोर्चे के निर्माण की पूर्व शर्त है। 17वीं पार्टी कांग्रेस के राजनीतिक प्रस्ताव ने इंगित किया था कि :

"सीपीआइ(एम) की बढ़त और इसकी अखिल भारतीय शक्ति में इजाफा किये बिना, वामपंथी-जनवादी मोर्चे के निर्माण की दिशा में बढ़ना संभव नहीं है।"

32. मगर पार्टी की स्वतंत्र शक्ति के विकास के मामले में प्रगति करने में हम असमर्थ रहे हैं। पिछले ढाई दशक में पार्टी सदस्यता एवं अखिल भारतीय वर्गीय एवं जनसंगठनों की सदस्यता में लगातार वृद्धि हुयी है। पार्टी सदस्यता 14 वीं पार्टी कांग्रेस के समय 5.8 लाख थी जो 21वीं कांग्रेस के समय बढ़कर 10.58 लाख हो गयी। जन संगठनों की कुल सदस्यता 14वीं पार्टी कांग्रेस के समय 2. 88 करोड़ थी, जो बढ़कर 21वीं पार्टी कांग्रेस तक 5.31 करोड़ हो गयी। मगर यह वृद्धि मुख्यत: तीन राज्यों - पश्चिम बंगाल, केरल, त्रिपुरा में ही केंद्रित रही। इन तीनों राज्यों की पार्टी सदस्यता कुल पार्टी सदस्यता का 73 प्रतिशत है। इन तीनों राज्यों के जनसंगठनों की सदस्यता कुल अखिल भारतीय सदस्यता का 76 प्रतिशत है। इसी तरह अगले दो मजबूत राज्यों- तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश (अविभाजित)-में पार्टी तथा जनसंगठनों की सदस्यता में वृद्धि, जनता के बीच प्रभाव में तथा जनसांगठनिक पार्टी की स्वतंत्र शक्ति में, किसी खास विकास का

संकेत नहीं देती है। चुनावी पैमाने पर इन दोनों राज्यों में गिरावट ही आयी है।

33. इसी वजह से 18वीं पार्टी कांग्रेस (2005) की राजनीतिक-सांगठनिक रिपोर्ट में दर्ज किया था:

"पार्टी सदस्यता में बढ़त, जनसंगठनों की सदस्यता, पार्टी एवं जनसंगठनों की लामबंदी की क्षमता और पार्टी की चुनावी शक्ति यह नहीं प्रदर्शित करती कि इस अवधि में पार्टी ने कोई विस्तार किया है। कुल मिलाकर स्थिति यह है कि मजबूत राज्यों में पार्टी अपनी शक्ति को कायम रखे हुए है और कमजोर राज्यों तथा इलाकों में धीरे-धीरे गिरावट की स्थिति में है।"

तबसे लेकर कमजोर राज्यों में स्थिति में कोई सुधार नहीं है जबकि, इसी के साथ, हमें पश्चिम बंगाल में समर्थन में क्षरण का सामना करना पड़ा है।

नव-उदार पूंजीवाद का दौर

34. मजदूर वर्ग, किसानों, मजदूरों तथा मेहनतकश अवाम के अन्य हिस्सों को लामबंद करते हुए हम नव-उदार नीतियों तथा पूंजीवादी-सामंती राज के खिलाफ संघर्ष का कार्यभार सामने रखते रहे हैं। इसी के साथ हमें वैचारिक संग्राम तथा सामाजिक उत्पीड़न के खिलाफ संघर्ष भी चलाना होगा। पार्टी का आगे बढ़ना तथा स्वतंत्र विकास मूलतः इन संघर्षों एवं आंदोलनों की बढ़त पर निर्भर करता है।

35. 1991 में उदारीकरण और नव-उदार नीतियों के उद्भव के साथ ही पूंजीवादी विकास के परिप्रेक्ष्य में पूरी तरह से बदलाव आ गया है। नयी प्रौद्योगिकीय खोजों तथा सूचना प्रौद्योगिकी ने उत्पादन प्रणाली एवं समाज पर गहरा प्रभाव डाला है। नव-उदार पूंजीवाद के इस दौर की व्यापक समझदारी तक पहुंचने में देरी हुयी है। इन गहरे परिवर्तनों तथा विभिन्न वर्गों पर हुए इनके प्रभावों का विश्लेषण किये बिना मजदूर वर्ग, किसानों, युवाओं, छात्रों, महिलाओं एवं अन्य तबकों के विभिन्न जनांदोलनों के विकास हेतु जरूरी सही नारे तथा कार्यनीति विकसित कर पाना संभव नहीं है । हालांकि हमने कहा था कि "हमारा मुख्य काम जनता के विभिन्न हिस्सों को प्रभावित करने वाले नव-उदार नीतियों के सारे पहलुओं से लड़ना है" (20 वीं कांग्रेस), हम इसे समुचित तरीके से सम्बोधित नहीं कर सके और जनांदोलनों एवं वर्ग संघर्ष को विकसित करने के लिए सटीक कार्यनीति एवं नारों का सूत्रीकरण नहीं कर सके। केंद्रीय समिति की समीक्षा रिपोर्ट में लिए गए

निर्णय के अनुसार हमने विभिन्न वर्गों एवं क्षेत्रों में हुए परिवर्तनों का ठोस अध्ययन किया है। इसके आधार पर हमें ठोस नारे एवं कार्यनीति तय करने में समर्थ होना चाहिए।

36. अद्यतन पार्टी कार्यक्रम में हमने दर्ज किया था कि देहाती इलाकों में एक ग्रामीण धनाढ्य गठजोड़ है जिसमें जमींदार, धनी किसान, ठेकेदार, बड़े व्यापारी इत्यादि शामिल हैं। यही वे तबके है जिसके साथ गरीब किसानों एवं खेत मजदूरों के अंतर्विरोध बढ़े हैं। क्या हम गरीब किसानों तथा खेत मजदूरों के मुद्दों को उठाने एवं आंदोलन को इस दिशा में मोड़ने में सफल हुए ? ऐसा करने में विफल रहने के कारणों में से एक इस तथ्य से भी जुड़ा है कि हम इस ग्रामीण धनाढ्य वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाली क्षेत्रीय पार्टियों को अपने संभावित चुनाव सहयोगियों के रूप में देखते रहे।

37. नव-उदार नीतियां शासक वर्गों के इशारे पर लागू की जा रही हैं। ये किसी एक केंद्र सरकार द्वारा लागू की गयी नीतियां नहीं है। 1991 की नरसिम्हाराव सरकार के बाद से आयी सभी सरकारें इसी रास्ते पर चली हैं। हमने समय-समय पर इस पहलू को कम करके आंका। साम्प्रदायिक खतरे को दूर रखने के नाम पर हम यूनाइटेड फ्रंट सरकार के उस साझा न्यूनतम कार्यक्रम के हिस्से बन गए, जिसकी मुख्य दिशा उदारीकरण तथा निजीकरण की नीतियों पर चलने की थी। इसके बाद 2004 में हमने यूपीए सरकार को बाहर से समर्थन दिया-जो सही कदम था। हालांकि यूपीए सरकार का मुख्य जोर भी साझा न्यूनतम कार्यक्रम के जरिये नव-उदार नीतियों को अमल में लाने का था।

38. नव-उदार नीतियों के विरुद्ध संघर्ष का एक और पहलू वाम नेतृत्व वाली सरकारों द्वारा अपनाये जाने वाले रुख और नीतियों से सम्बंधित है। पश्चिम बंगाल की वाम मोर्चा सरकार- जो हमारे नेतृत्व में सबसे लम्बे समय तक चलने वाली सरकार थी -को इस सवाल का सामना करना पड़ा था। यह समस्या औद्योगीकरण के लिए भूमि अधिग्रहण के समय सामने आयी। नंदीग्राम एवं कुछ अन्य परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण के प्रस्ताव के चलते किसानों के हिस्सों से अलगाव हुआ। अखिल भारतीय स्तर पर इसे नव-उदार राज में भूमि हथियाने के कार्पोरेट एजेंडे के हिस्से के रूप में देखा गया। पश्चिम बंगाल में इस मुद्दे की हमने बड़ी कीमत चुकाई। पार्टी की अखिल भारतीय छवि पर भी इसका बुरा असर पड़ा। वाम मोर्चा सरकार के उस आख़िरी दशक में, जब नव-उदार नीतियां आ चुकी

थीं, वाम मोर्चा सरकार द्वारा अपनाई गयी नीतियों के आलोचनात्मक परीक्षण की आवश्यकता है। हमें समुचित सबक लेने की जरूरत है ताकि भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर हम सही रास्ता उपलब्ध करा सकें।

39. यह स्वीकार करना होगा कि वैश्वीकरण-नव-उदारवादी राज में जारी प्रक्रियाओं ने वाम के समक्ष नयी चुनौतियां प्रस्तुत की हैं और मजदूर वर्ग, खेतिहरों, छात्रों, युवाओं तथा महिलाओं के आंदोलनों को विकसित करने में प्रतिकूल स्थितियां खड़ी की हैं। यह जरूरी हो जाता है कि हम इन प्रक्रियाओं को समझें और नयी तथा माकूल कार्यनीति एवं सांगठनिक विधियां तैयार करें । यही पार्टी की स्वतंत्र शक्ति के विकास का आधार होगा।

पी-टीएल के अमल में चूकें

40. पी-टीएल के विभिन्न पहलुओं को अमल में लाते समय, कई बार आकलन में गलतियां तथा चूकें हुई हैं। विभिन्न आम चुनावों में हम प्रचलित कार्यनीति के आधार पर चुनावी कार्यनीति अपनाते रहे। बाद में इनकी समीक्षा की गयी और कुछ गलतियों की पहचान की गयी। उदाहरण के लिए 1999 के लोकसभा चुनाव की समीक्षा में दर्ज किया गया कि चुनाव अभियान के दौरान हमारे कुछ नेताओं के कथनों ने ऐसा आभास दिया कि जैसे हम कांग्रेस समर्थक लाइन पर चल रहे हैं। आत्मालोचनात्मक तरीके से दर्ज किया गया कि इस तरह के वक्तव्यों से यह प्रभाव गया कि जैसे हम कांग्रेस के साथ सहयोग के इच्छुक हैं और चुनाव के पश्चात तीसरे विकल्प के निर्माण के प्रति गंभीर नहीं हैं। चुनाव के दौरान पार्टी केंद्र द्वारा कांग्रेस की ताकत को भी अधिक करके आंका गया था। 2009 के लोकसभा चुनाव की समीक्षा में हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि जब राष्ट्रीय पैमाने पर कोई भरोसेमंद चुनावी विकल्प मौजूद ही नहीं था, हमारा वैकल्पिक सरकार का नारा देना सही नहीं था।

41. कार्यनीति के अमल में भी कुछ चूकें थीं। 1996-98 के काल में जब हम यूनाइटेड फ्रंट की सरकार का समर्थन कर रहे थे, उस अवधि की अपनी भूमिका की अपनी समीक्षा में हम इस नतीजे पर पहुंचे थे कि हम सरकार की उदारीकरण समर्थक नीतियों से खुद को पर्याप्त तरीके से अलग दिखाने में विफल रहे थे। वहीं सरकार को बनाये रखने में हमारी व्यस्तता का परिणाम जनसंघर्षों तथा जनआंदोलनों के विकास से भी हमारा ध्यान भटकने के रूप में सामने आया।

42. जुलाई 2008 में यूपीए सरकार से समर्थन वापस लिए जाने के सवाल पर 20वीं पार्टी कांग्रेस ने इस निर्णय की समीक्षा करते हुए निष्कर्ष निकाला था उस समय समर्थन वापसी के सिवाय और कोई रास्ता नहीं था। किन्तु समर्थन वापसी अक्टूबर–नवम्बर 2007 में उसी समय कर ली जानी चाहिए थी जब सरकार वार्ताओं के लिए आइएईए जाना चाहती थी। उस समय ऐसा न करना एक गलती थी। पीबी और सीसी ने रणनीतिक गठबंधन के अंग के रूप में की जा रही न्यूक्लियर डील को हासिल करने की शासक वर्गों एवं अमरीकी साम्राज्यवाद की क्षमता और संकल्प को कम करके आंका। घटनाक्रम को प्रभावित करने की अपनी ताकत एवं क्षमता को भी हमने ज्यादा करके आंका। सरकार को वार्ताओं के लिए आइएईए तक जाने देना और कांग्रेस से यह उम्मीद करना कि वह इस करार के आधार पर परिचालन न करने की समझदारी से बंधी रहेगी, गलत था।

43. जैसा कि अन्य सन्दर्भ में इंगित किया गया है, साम्प्रदायिक शक्तियों के विरुद्ध गतिविधियां विकसित करने के मामले में कमजोरियां रहीं। हालांकि पी–टीएल ने साम्प्रदायिक शक्तियों का प्रत्युत्तर देने का निर्देश दिया था, किन्तु जमीनी स्तर पर, विशेषकर सामाजिक एवं सांस्कृतिक दायरे में, साम्प्रदायिक शक्तियों के मुकाबले हेतु ठोस कदम उठाये जाने के मामले में कोशिशें अपर्याप्त रहीं। इसी तरह, कार्यनीति में दिए गए निर्देश के बाद भी, पार्टी द्वारा सामाजिक मुद्दों के उठाए जाने में विफलता को पार्टी कांग्रेसों में लगातार दर्ज किया गया है। हम ठोस तथा पर्याप्त तरीके से मजदूर–किसान गठबंधन के नारे को लागू नहीं कर पाए हैं। सामने आयी विभिन्न कठिनाइयों के चलते हम वर्गीय व जनसंगठनों के संयुक्त मंच, जैसे जनसगठनों के राष्ट्रीय मंच (एन पी एम ओ) को आगे नहीं ले जा पाए हैं।

44. पी–टीएल को अमल में लाने में तथा उससे निकलने वाली चुनावी कार्यनीति में हुई इस प्रकार की चूकों और त्रुटियों ने भी, कार्यनीतिक लक्ष्य की ओर बढ़ पाने में हमारी अक्षमता में योग दिया है।

साम्प्रदायिकता के विरुद्ध संघर्ष

45. भाजपा जब सत्ता में हो तब हमारे हमलों की मुख्य धार उसी पर होनी चाहिए, मगर इसका मतलब कांग्रेस के साथ चुनावी समझदारी बनाना नहीं है। ना ही इस तरह का रुख होना चाहिए कि नव–उदार नीतियों से लड़ने का मुख्य काम

साम्प्रदायिकता से लड़ने के काम के अधीन हो जाए। साम्प्रदायिकता से लड़ने और जनता की जीविका के लिए नव-उदार नीतियों के खिलाफ लड़ने के प्रति हमारे रवैये में किसी भी तरह का द्वैध नहीं होना चाहिए। आर एस एस और भाजपा के विरुद्ध लड़ाई सिर्फ चुनावी कार्यनीति तक सीमित नहीं रखी जानी चाहिए। यह मेहनकश जनता की एकता को बिखेरने वाली साम्प्रदायिकता के विरुद्ध हमारी लड़ाई का हिस्सा है। शासक वर्गों द्वारा इसका उपयोग, नव-उदार नीतियों तथा पूंजीवादी-सामंती राज की वजह से उत्पन्न हुए असंतोष को भटकाने के लिए भी किया जाता है। बहुसंख्यक साम्प्रदायिकता, अल्पसंख्यक साम्प्रदायिकता की ओर ले जाती है, इसलिए उसके मुकाबले की भी आवश्यकता है। हमारी समझ में नव-उदार नीतियों और साम्प्रदायिकता के खिलाफ लड़ाई एक दूसरे से जुडी हुयी हैं। जनता की जीविका के लिए संघर्ष और साम्प्रदायिक शक्तियों तथा हिंदुत्व की विचारधारा के विरुद्ध लड़ाई को एकीकृत करने का दृष्टिकोण होना चाहिए। इन संघर्षों को एकीकृत करके ही हम साम्प्रदायिकता के विरुद्ध जन समर्थन जुटा सकते हैं। सामाजिक नजरिये से, हिन्दुत्ववादी साम्प्रदायिकता से लड़ाई, जाति एवं महिला उत्पीड़न के खिलाफ संघर्षों की दरकार रखती है, क्योंकि हिंदुत्व की विचारधारा में जाति व्यवस्था और पितृसत्तात्मकता सन्निहित हैं।

46. साम्प्रदायिक शक्तियों द्वारा पेश किये जा रहे खतरों को देखते, जो भाजपा के लोकसभा में पूरे बहुमत के साथ सत्ता में आने से और बढ़ गए हैं, हमें धर्मनिरपेक्ष और लोकतान्त्रिक शक्तियों की व्यापक एकता कायम करने के लिए प्रयास करना चाहिए। इस तरह के संयुक्त मंच साम्प्रदायिकता के खिलाफ व्यापक लामबंदी के हिसाब से जरूरी हैं। बहरहाल, इस तरह के मंचों को चुनावी गठबंधनों के आधार के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।

संसदवाद

47. संसदवाद एक सुधारवादी नजरिया है जो पार्टी के कामकाज को सिर्फ चुनावी काम तक सीमित करता है और यह भ्रम फैलाता है कि पार्टी सिर्फ चुनाव लड़कर ही आगे बढ़ सकती है। यह जन आंदोलनों को संगठित करने, पार्टी के निर्माण तथा वैचारिक संघर्ष के काम की अनदेखी की दिशा में ले जाता है। जनांदोलनों एवं राजनीतिक संघर्षों को मजबूत बनाने के लिए संसदीय एवं संसदीय-इतर कामों को एक साथ किये जाने की आवश्यकता है।

48. पी-टीएल को इस पहलू पर समुचित ध्यान देना चाहिए। अगर मुख्य ध्यान पार्टी की स्वतंत्र भूमिका बढ़ाने और वामपंथी-लोकतांत्रिक मोर्चे (जो एक वर्गीय आधार पर बना गठबंधन है, चुनावी गठबंधन नहीं है) के निर्माण पर केंद्रित रखना चाहते हैं तो आज, चुनावी दांवपेंच पर केंद्रित रहने, पूंजीवादी पार्टियों के साथ चुनावी गठबंधन बनाने की कोशिशें करने और एक ऐसे विकल्प को सामने लाने जो सिर्फ चुनावी प्रकृति का है, का जो व्यवहार हम देख रहे हैं, उस से हमें बचना होगा।

49. नव-उदार ढांचे में राजनीति में बड़े पैसे और मीडिया के प्रवेश के साथ संसदीय लोकतंत्र को सीमित किया जा रहा है। इसे ध्यान में रखे जाने की जरूरत है। इसका मतलब चुनावी मैदान में अपने काम को नजरअंदाज करना या उसको कम करके आंकना नहीं है । असल में तो, पार्टी को चुनावी संघर्षों के दौरान अपनी स्वतंत्र भूमिका को, राजनीतिक रूप से, अधिक दमदारी के साथ प्रस्तुत करना चाहिए। स्वतंत्र भूमिका तथा गतिविधियों के न होने और उनमें से वर्गीय एवं जन संगठनों को विकसित न कर पाने की और नतीजे में अपना सांगठनिक सुदृढ़ीकरण न कर पाने की कमजोरी के चलते चुनावी मैदान में हमारा काम कमजोर तथा अपने संगठन में दरिद्र है।

सारांश

50. अब तक अपनाई गयी राजनीतिक-कार्यनीतिक नीतियों (पी-टीएल) ने हमें उस समय की स्थितियों का सामना करने एवं सही चुनावी कार्यनीति बनाकर कांग्रेस तथा भाजपा का मुकाबला करने में मदद पहुंचाई है। इन राजनीतिक-कार्यनीतिक लाइनों ने वामपंथी एकता को मजबूत बनाने और वाम नेतृत्व वाली राज्य सरकारों के गठन तथा उन्हें मजबूत करने में मदद दी है।

51. मेहनतकश जनता के संघर्षों तथा आंदोलनों को जरूरी दिशा एवं गति देने में कमजोरी, नव-उदार पूंजीवाद के समाज एवं वर्गों पर हुए असर को समझने में देरी के चलते रही।

52. पी-टीएल वामपंथी, जनवादी एवं धर्मनिरपेक्ष पार्टियों के गठबंधन का कार्यभार तय करती रही, जिसे साझा कार्यक्रम पर आधारित तीसरे विकल्प जैसे अंतरिम मोर्चे तक आगे बढ़ा दिया गया। यह इच्छा निष्फल साबित हुयी और इसने आंदोलनों, संघर्षों के आधार पर पार्टी के स्वतंत्र विकास पर जोर देने से ध्यान

बंटाया। समय-समय पर इसने एक के बाद एक आयी सरकारों की नव-उदार नीतियों के विरुद्ध लड़ाई की प्राथमिकता को कम करके आंका।

53. इसका एक बड़ा परिणाम यह निकला वाम-जनवादी मोर्चे को एक हासिल किये जाने योग्य लक्ष्य से घटाकर एक प्रचारात्मक नारे तक सीमित कर दिया गया। इसने अनवरत संघर्षों के निर्माण, नव-उदार राज से पीड़ित मेहनतकश अवाम के विभिन्न हिस्सों की संयुक्त कार्यवाहियों तथा साम्प्रदायिकता के विरुद्ध समन्वित रूप से जमीनी स्तर पर लड़ाई के मुख्य काम से दूर हटाया।

उठाये जाने वाले कदम

54. कार्यनीतिक लाइन (पी-टीएल) का आलोचनात्मक पुनर्परीक्षण हमें निम्नलिखित निष्कर्षों तक पहुंचाता है;

55. वामपंथी जनवादी मोर्चे और वर्गों को उसके पीछे लामबंद किये जाने वाले कार्यक्रम की प्राथमिकता बहाल की जानी चाहिए। हमें इसके गठन की प्रकृति (चूंकि इसके बारे में आख़िरी कोशिश 10 वीं पार्टी कांग्रेस में की गयी थी) के बारे में और अधिक सोच-विचार करना चाहिए। इसी के अंग के रूप में हमें वामपंथी एकता को और अधिक व्यापक तथा प्रगाढ़ करना चाहिए।

56. पार्टी की स्वतंत्र भूमिका एवं इसकी ताकत तथा जनाधार को बढ़ाना प्राथमिकता पर लिया जाना चाहिए।

57. मजदूरों, किसानों, खेत मजदूरों के वर्ग संघर्षों एवं जनता के हिस्सों के जन संघर्षों को विकसित करने हेतु ठोस नारे एवं कार्यनीति बनाई जानी चाहिए। यह काम इस बीच सामने आये परिवर्तनों के ठोस अध्ययन के आधार पर किया जाना चाहिए।

58. आगामी राजनीतिक-कार्यनीतिक लाइन (पी-टीएल) को हिन्दुत्ववादी शक्तियों एवं साम्प्रदायिक विचारधारा के विरुद्ध राजनीतिक, वैचारिक तथा सांगठनिक धरातल पर संघर्ष के लिए ठोस दिशा एवं विषयवस्तु देने वाली होना चाहिए।

59. राजनीतिक-कार्यनीतिक लाइन (पी-टीएल) को जातिवादी उत्पीड़न के खिलाफ संघर्ष तथा पहचान की राजनीति के मुकाबले हेतु ठोस दिशा-निर्देश देने चाहिए। महिलाओं के अधिकारों के लिए एवं लैंगिक उत्पीड़न के विरुद्ध लड़ाई पर और

अधिक जोर दिया जाना चाहिए। पार्टी को बड़े पैमाने पर सामाजिक मुद्दे उठाने चाहिए तथा दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक और पिछड़े समुदायों के मुद्दों पर, जरूरी विशेष हस्तक्षेप सुनिश्चित किये जाने चाहिए।

60. राजनीतिक-कार्यनीतिक लाइन (पी-टीएल) को वर्गीय संगठनों एवं जनसंगठनों के संयुक्त आंदोलनों आंदोलनों को और जन मुद्दों को लेकर संयुक्त कार्यवाहियों एवं साझा मंचों के पार्टी के प्रयत्नो को दिशा देनी चाहिए।

60. चुनावी कार्यनीति को वामपंथी जनवादी मोर्चे के निर्माण की प्राथमिकता से मेल खाने वाला होना चाहिए। वर्तमान स्थिति में क्षेत्रीय पार्टियों की भूमिका को देखते हुए उनके साथ राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन बनाने का कोई आधार नहीं है। इसके बजाय उन राज्यों में गैर-वामपंथी पार्टियों धर्मनिरपेक्ष पार्टियों के साथ ऐसा चुनावी तालमेल किया जा सकता है जहां पार्टी हित के हिसाब से यह आवश्यक हो और राज्य में वाम- जनवादी शक्तियों को लामबंद करने में मदद पहुंचाए।

62. राजनीतिक-कार्यनीतिक लाइन (पी-टीएल) पर अमल, पार्टी संगठन एवं उसकी ऐसा करने के लिहाज से उसकी कारगरता पर निर्भर करता है। जनता के बीच काम करने और उसे वर्ग संघर्षों-जन संघर्षों में खींच लाने तथा जन प्रभाव को राजनीतिक रूप सुदृढ़ीकृत करने के लायक संगठन के बिना, कार्यनीतिक लाइन सही तरीके से लागू नहीं की जा सकती है। पार्टी कार्यकर्ताओं का वैचारिक स्तर भी एक प्रमुख कारक है। हमें हर स्तर पर पार्टी संगठन तथा कार्यप्रणाली के तरीकों की स्थिति का आलोचनात्मक परीक्षण करना होगा। इसके आधार पर, हमें संगठन को नयी गति देनी होगी तथा जनता के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचने की नयी विधियां खोजनी होंगी। वर्गीय संगठनों एवं जन संगठनों के सही अनुकूलन, उनकी स्वतंत्र कार्यप्रणाली तथा जनसंगठनों के प्रति पार्टी का सही दृष्टिकोण सुनिश्चित करना होगा। 21वीं पार्टी कांग्रेस में मौजूदा राजनीतिक-कार्यनीतिक लाइन को स्वीकार करने के बाद संगठन पर होने वाला प्लेनम, इस महत्वपूर्ण काम को पूरा करेगा।